

न्यायालय में :- श्रीमान, राजव मंडल महोदय,

गवालियर मओप्रओ

67



CF. Rs. 20/-

2985-I/2004

1. दददी सिंह | दोनों पिता चरका गौड़  
साहब सिंह

दोनों निवासी अमलई तहसील-अनूपपुर जिला-अनूपपुर मओप्रओ  
----- आवेदक गण

जनरल कलेक्टर, संदीपी  
29 JUL 2004  
मा. टी. भा. ए.  
कनाड  
पु. 10/09/04  
रा. 10/09/04  
वि. 10/09/04

बनाम

1. सुंदरी पत्नी स्व० रामजियावन  
दिनेश अर्प ठाकुर

सभी पिता स्व० रामजियावन

3. महेश  
4. रजनीबाई  
5. बाई जी छ्नी चरका गौड़

सभी निवासी अमलई पो०-पयारी तहसील-अनूपपुर जिला-  
अनूपपुर मओप्रओ ----- अनावेदक गण

29/7/04  
रा. 29/7/04  
वि. 29/7/04  
मओप्रओ

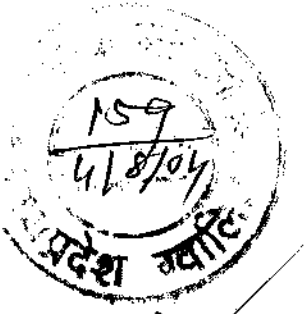
निगरानी विरुद्ध निर्णय न्यायालय आयुक्त  
महोदय, रीवा संभाग रीवा रा० प्र० क्र०  
133/निग०/2003-04 एवं रा. 24.4.04/9

निर्णय विरुद्ध कलेक्टर महोदय, जिला-अनूपपुर  
रा. 106/02-03 एवं प्र० क्र० 105/  
निग०/02-03 आदेश दिनांक 11.11.2003

RL. 1721  
पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 11/11/04  
को प्राप्त  
रा. 11/11/04  
वि. 11/11/04  
मओप्रओ

मा. न्ये. र,  
आवेदक गण निम्नलिखित कार्यों से निम्न निगरानी  
प्रस्तुत कर प्रार्थी हैं :-

- 1. यह कि प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानूनन एवं वाक्यातन गलत है।
- 2. यह कि प्रत्येक अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु



अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक	निगम 985 एक / 2004	जिला - अनूपपुर
स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-6-2016	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण 133/निगम/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2004 के विरुद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।</p> <p>2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार फुनगा, जिला-अनूपपुर के समक्ष नामांतरण हेतु आवेदन-पत्र पेश किया गया, जो प्रकरण क्रमांक 17/अ-6/91-92 में पारित आदेश दिनांक 24.04.92 को इस आशय से आवेदन-पत्र अस्वीकार किया कि संहिता की धारा 110 तथा 32 के तहत एक बार नामांतरण हो चुका है। पुनः नामांतरण नहीं किया जा सकता। सिविल वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रकरण खारिज किया गया। इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर शहडोल के समक्ष प्रकरण क्रमांक 17/अ-6/91-92 में पारित आदेश दिनांक 24.04.92 स्वप्रेरणा में निगरानी में लेने हेतु संहिता की धारा 50 एवं 32 के तहत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को सुनने के उपरांत प्रकरण स्वप्रेरणा में चलने योग्य न होने से अपास्त किया गया। न्यायालय अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा आयुक्त रीवा संभाग रीवा के यहाँ निगरानी पेश की गई। प्रकरण क्रमांक 133/निगम/2003-04 किया गया। यहाँ पर भी ठोस आधार</p>	

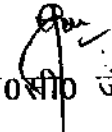
के अभाव में पारित आदेश दिनांक 24.04.2004 को निगरानी निरस्त की गई । इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला-अनूपपुर के समक्ष नायब तहसीलदार तहसील फुनगा, तहसील अनूपपुर के प्रकरण क्र० 17/अ-6/91-92 में पारित आदेश दिनांक 24.04.92 को स्वमेव निगरानी में लिये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया था, जो अमान्य किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि प्रश्नाधीन भूमि चरका गौड के एकाकी मालिका व स्वामित्व की रही है । चरका गौड आवेदकगण के पिता थे । रामजियावन, चरका गौड का न तो वारिस उत्तराधिकारी था और ना ही किसी प्रकार की रिश्तेदारी थी । ऐसी स्थिति में रामजियावन के वारिसों को बंटवारा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था । गैर कानूनी तरीके से पारित आदेश के विरुद्ध प्रकरण को स्वयमेव निगरानी में लेने का पूर्ण अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को रहा है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विरुद्ध आदेश पारित करने की भूल की है जो निरस्तीय योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे ।

4/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । जिससे यह स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार फुनगा, जिला-अनूपपुर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ-6/91-92 में पारित आदेश दिनांक 24.04.92 से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में नामांतरण आदेश पारित किया था, जो अंतिम स्वरूप होकर म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के तहत

अपीलीय योग्य था । आवेदकगण द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध समक्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत न कर तहसीलदार के समक्ष ही प्रकरण स्वमेव निगरानी हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था । संहिता की धारा 51 के अनुसार प्रकरण स्वमेव निगरानी में किसी व्यक्ति के आवेदन-पत्र पर लिये जाने का प्रावधान नहीं । इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण का स्वमेव निगरानी आवेदन-पत्र निरस्त किया गया है । अपर कलेक्टर शहडोल के आदेश दिनांक 11.11.03 एवं आरक्षक रीवा के आदेश दिनांक 24.04.2004 में कोई त्रुटि प्रदर्शित नहीं होती । अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश उचित होने के कारण उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को यथावत रखते हुये निगरानी खारिज किया जाता है ।

  
(के०सी० जैन)  
सदस्य